www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 20 | जौनपुर, गुरूवार, 03 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

भारत ने भेजी 5वीं राहत खेप, 166 भारतीय सुरक्षित निकाले गए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दो सितंबर भारत ने गुरूवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल को पांच टन से अधिक जरूरी दवाइयों की पांचवीं खेप और 11 सदस्यों वाली बचाव टीम भेजी। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार, पिछले सप्ताह आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है। बचावकर्मियों ने प्रभावित इलाकों से और शव बरामद किए हैं। आपातकालीन दलों ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं और खोज एवं बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, मानवीय सहायता लेकर भारतीय वायुसेना का पांचवां विमान आज काठमांडू पहुंचा। इसमें करीब 5.5 टन चिकित्सा सामग्री शामिल है, जिसमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवाएं, शल्य चिकित्सा से जुड़ी सामग्री और अन्य जरूरी दवाइयां शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि विमान में 11 सदस्यों की एक विशेष टीम और छह टन से अधिक बचाव का सामान भी था। भारत अब तक नेपाल को करीब 74 टन राहत सामग्री उपलब्ध करा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 166 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है, जिनमें बुधवार को बचाए गए तीन लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तीर्थयात्रा या अन्य गतिविधियों के लिए गए कुल 410 भारतीय नागरिक बुधवार को चीन से रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय सुरंग बचाव दल के काम के बारे में भी जानकारी दी। इसने कहा, भारतीय सुरंग बचाव दल ने आज अपना आधार बदलकर त्रिशूली से स्याब्रूबेसी कर लिया है, जिससे चिलिमे तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जहां बचाव अभियान जारी है। इसमें कहा गया है, दल ने नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलिमे में अपना तलाशी अभियान जारी रखा। सुरंग के अंदर गहरी कीचड़ और अवरोधों के बावजूद दल आज लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने में कामयाब रहा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से बुधवार दोपहर पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया है और इसके नेपाली सेना के साथ समन्वय कर बृहस्पतिवार से अपना काम शुरू करने की उम्मीद है।

अवकाश सूचना

सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यालय व प्रेस में अवकाश रहेगा।

अतः अगला समय पर प्रकाशित होगा।

– सम्पादक

भारत और बेल्जियम सैन्य आदान-प्रदान व प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाएंगे - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भारत–बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम आधार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सैन्य आदान–प्रदान और प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पीएम मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने जोर दिया कि साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत, मजबूत बाजार अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों को "स्वाभाविक साझेदार" बनाते ह बातचीत के रणनीतिक नतीजों के बारे में विस्तार से बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, "रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मुख्य स्तंभ है। आज, हमने दोनों देशों के बीच सैन्य आदान–प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हमारी सरकारों और रक्षा उद्योगों के बीच हुए समझौते रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास और उत्पादन के नए अवसर खोलेंगे। हम अपनी–अपनी एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और अपराध के खिलाफ सहयोग को भी और मजबूत करेंगे।" पिछले दस वर्षों में राजनयिक संबंधों में आए उल्लेखनीय बदलावों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा नवाचार और टिकाऊ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गया है। उन्होंने जोरावर लाइट टैंक जैसे उन्नत सैन्य हार्डवेयर से जुड़े सहयोगी प्रोजेक्ट्स और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक प्रमुख ग्रीन अमोनिया सुविधा के विकास जैसी बड़ी आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "भारत और बेल्जियम के संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान हमारी साझा यादों का एक अहम हिस्सा है। आज, लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच मजबूत संबंध हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं।"

बीएलओ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार स्तंभ – सीईसी ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मतदाता सूची की तैयारी और चुनावों का संचालन भारत के संविधान, कानून और ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को गोवा में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) से संवाद किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये 1000 से अधिक बीएलओ इस बातचीत में शामिल हुए। इस अवसर पर बीएलओ की भूमिकाओं को कोकणी में और बीएलए की भूमिकाओं को अंग्रेजी में समझाने वाले छोटे वीडियो भी जारी किए गए। इस दौरान, गोवा की समृद्ध परंपराओं और विरासत का जश्न मनाते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग और नागरिकों के बीच का पहला संपर्क बिंदु है। उन्होंने कहा कि गोवा के बीएलओ ने मतदाता सूची की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब भी निभा रहे हैं। वहीं, मतदाता सूची की ईमानदारी बनाए रखने के लिए बीएलओ की सराहना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूचियां, साथ ही पूरी चुनाव प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के प्रतिनिधि ा (बीएलए) और उम्मीदवारों के मतदान और मतगणना प्रतिनिधियों द्वारा एक साथ ऑडिट की जाती हैं। बैठक के हिस्से के रूप में बीएलओ ने सीईसी के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी किया।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एनएच–327 होगा फोरलेन, केंद्र ने 2,077 करोड़ रुपए किए मंजूर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–327 के 31.02 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन में बदलने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 2,077.18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना से उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक पहुंच बेहतर होगी। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि दार्जिलिंग जिले में एनएच–327 के बागडोगरा– पानीटंकी– खारीबाड़ी–गलगलिया खंड को फोरलेन में बदला जाएगा। 31.02 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर सड़क को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। परियोजना के तहत तीन बड़े पुल और एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाया जाएगा। इसके अलावा पांच एलिफेंट अंडरपास और सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने के साथ स्थानीय लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक होने के कारण इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फोरलेन सड़क बनने से पूर्वोत्तर भारत के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा। साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की ओर आवाजाही और व्यापारिक संपर्क को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

भारत–बेल्जियम रक्षा सहयोग को नई मजबूती, 10 बड़े समझौतों से बढ़ेगा सैन्य–औद्योगिक सहयोग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा सहयोग अब केवल राजनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं रहने वाला है। दोनों देश सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक के साथ–साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी साझेदारी को जमीन पर उतारने की तैयारी में हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर और रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन की भारत यात्रा के दौरान रक्षा उद्योग से जुड़े 10 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ 15 रक्षा कंपनियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इनमें से अधिकांश कंपनियों का प्रतिनिधित्व उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौतों के तहत बेल्जियम की कई रक्षा तकनीकों का भारत में उत्पादन और असेंबली शुरू होने की संभावना है। इनमें रॉकेट, गोला–बारूद, हथियार प्रणालियां, ड्रोन, रडार और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी तकनीक शामिल हैं। बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भारत को हिंद–प्रशांत क्षेत्र की एक तेजी से उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति बताते हुए कहा, "यूरोप और एशिया की सुरक्षा अब एक–दूसरे से अलग नहीं देखी जा सकती। रूस–यूक्रेन में युद्ध जारी है और वह ईरान तथा उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। वहीं चीन हिंद–प्रशांत में लगातार अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है। ऐसे में एशिया में होने वाली घटनाओं का असर यूरोप पर और यूरोप की घटनाओं का असर एशिया पर पड़ता है।" फ्रांकेन के मुताबिक, बेल्जियम जैसे खुले व्यापार वाले देश के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा बेहद जरूरी है इसलिए भारत जैसे मजबूत साझेदार के साथ सैन्य, तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत है। भारत और बेल्जियम के बीच मौजूदा रक्षा पहल की नींव पिछले आर्थिक मिशन के दौरान रखी गई थी। उस दौरान दोनों देशों की कंपनियों के बीच संपर्क बढ़ा और राजनीतिक स्तर पर भी सहयोग के रास्ते खुले।

रेखा गुप्ता ने कहा, अब दिल्ली में कारोबार शुरू करना हुआ बेहद आसान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी। इसका मकसद राजधानी में कारोबार के लिए मंजूरी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दूसरी जरूरी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर किए गए इस बिल में एक सिंगल–विंडो ऑनलाइन सिस्टम का प्रस्ताव है। इसके जरिए बिजनेस अलग–अलग तरह की मंजूरी, रजिस्ट्रेशन, नो–ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइसेंस और दूसरी जरूरतों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्रस्तावित सिस्टम के लिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी होगी। प्रस्तावित कानून के तहत, शेड्यूल–3 में बताई गई कम जोखिम वाली कई गतिविधियों के लिए आवेदन जमा करते ही मंजूरी, अनुमति, लाइसेंस या छूट दे दी जाएगी। तय सीमा के अंदर आने वाली कुछ कम जोखिम वाली गतिविधियों और मामलों के लिए स्व–घोषणा भी स्वीकार की जाएगी। जो गतिविधियाँ शेड्यूल–3 में शामिल नहीं हैं, उनके लिए श्नागरिकों को समय पर और आसानी से सेवाएँ देने का अधिकार अधिनियम, 2026 के तहत तय समय–सीमा में मंजूरी देनी होगी। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि अगर सक्षम अधिकारी तय समय–सीमा में फैसला नहीं ले पाते हैं, तो मंजूरी मिल गई मान ली जाएगी। इस प्रस्तावित कानून का मकसद व्यवसायों पर कई तरह के रजिस्ट्रेशन का बोझ कम करना है। जो कंपनियाँ पहले से ही ळैज् व्यवस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम या लेबर कोड के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें व्यापार, हेल्थ ट्रेड, ईटिंग हाउस या दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इस बिल में भरोसे पर आधारित इंस्पेक्शन सिस्टम का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद तीन साल तक कोई रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा।

पूंजीगत परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे के विकास से उद्योग को समर्थन जारी रखना सरकार की प्राथमिकता – सीतारमण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए उद्योग को निरंतर समर्थन देना भारत सरकार के आर्थिक एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने यह बात एक निवेशक राउंडटेबल के दौरान कही। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और बैंक ऑफ अमेरिका के सहयोग से आयोजित उच्चस्तरीय बिजनेस राउंडटेबल को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने घरेलू नीतिगत उपायों का उल्लेख किया, जो आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से विमानन क्षेत्र के माध्यम से उद्योग को निरंतर समर्थन देनाय अनुकूल और निवेश के लिए सहायक माहौल को बढ़ावा देनाय एआई और डेटा केंद्रों के विकास को प्रोत्साहित करनाय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों को समर्थन देनाय एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करना।" वित्त मंत्री के अनुसार, इन कदमों से बैंकों और उद्योगों के लिए कारोबार करने, विस्तार करने और अपनी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिली है। वैश्विक चुनौतियों के बीच व्यापक आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने हालिया सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "वैश्विक व्यवधानों और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

आंकड़ों को तोड़–मरोड़कर पेश करने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता – पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जीडीपी डेटा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि आंकड़ों को एकत्रित करने की यह व्यवस्था वर्षों से चल रही है और इसमें राजनीतिक लोग शामिल नहीं होते हैं। साथ ही, कहा कि आंकड़ों को तोड़–मरोड़कर पेश करने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। एक्जिक्यूटिव ब्रांच ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि इस तरह से आंकड़ों को लेकर नकारात्मक सोच रखना अपनेआप को छोटा करना है और यह जनता के हौसले को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि यह सरकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का परिश्रम और सामर्थ्य है।उन्होंने आगे कहा कि देश की स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य इंडस्ट्री अच्छा कर रही हैं। निर्यात में भी करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनियों ने अच्छी आय बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। यह सभी देश में मजबूत मांग होने का संकेत हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने भी उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के आंकड़े को अच्छा दिखाने के लिए पिछले साल की पहली तिमाही की चालू जीडीपी के आंकड़े को संशोधित करके 86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो चालू कीमतों में जीडीपी की ग्रोथ 2.6 प्रतिशत थी।सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया।

डायट के मुख्य द्वार पर कूड़े का अंबार, जंगल के चलते प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षार्थियों की जिंदगी खतरे में शाम होते ही जंगल जैसे रास्ते पर पसरा जाता है सन्नाटा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।स्वच्छता को लेकर बड़े–बड़े दावे करने वाले नगर निगम की हकीकत देखनी हो तो जिला प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अयोध्या के मुख्य द्वार का नजारा ही काफी है।संस्थान में प्रवेश करते ही प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षको, कर्मियों व अन्य लोगो का स्वागत साफ–सुथरे परिसर से नहीं, बल्कि कूड़े–करकट के बदबूदार ढेर और गंदगी से होता है।मुख्य द्वार के आसपास फैली गंदगी व्यवस्था की पोल खोल रही है। स्थिति सिर्फ गंदगी तक सीमित नहीं है।डायट के आसपास जंगल क्षेत्र और झाड़ियों के बीच से होकर शिक्षार्थियों को आवागमन करना पड़ता है।ऐसे में बंदरों अथवा किसी अन्य जानवर के हमले की आशंका हर समय बनी रहती है।खासकर शाम ढलने के बाद यहां का माहौल और अधिक भयावह हो जाता है।रास्ते से गुजरने वाले शिक्षार्थियों और अन्य लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताती रहती है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस संस्थान में दूर–दराज से शिक्षार्थी प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं,वहां उनकी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों ने क्या इंतजाम किए हैं? यदि मुख्य द्वार और आसपास का क्षेत्र ही कूड़े, झाड़ियों और जंगलनुमा माहौल से घिरा रहेगा तो किसी अप्रिय घटना के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा?एक तरफ नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के दावे करता है, दूसरी तरफ जिला प्रशिक्षण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के मुख्य द्वार पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं संस्थान प्रशासन भी इस समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है।क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस गंदगी पर नहीं पड़ती? क्या संस्थान के अधिकारियों ने कभी मुख्य द्वार की इस दुर्दशा को गंभीरता से देखा? यदि देखा है तो अब तक सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई?प्रशिक्षार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर समस्या को अब और नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।परंतु महापौर, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और डायट के प्राचार्य की नजर इस गंभीर समस्या पर नहीं पड़ रही है'।

संपादकीय

विरोधी खेमों पर अब कोई असर नहीं

हकीकत से कटे नैरेटिव्स का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। जेन–जी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है। भारत का राजनीतिक विमर्श काफी पहले शालीनता की हदें तोड़ चुका है, इसलिए इसमें नए अपशब्दों के जुड़ने पर शायद ही किसी को एतराज होता है। तीखे ध्रुवीकरण की मौजूदा सूरत में किसी नेता की टिप्पणियों को गरिमा–विहीन या मर्यादा के खिलाफ बता कर उसे घेरने की रणनीति का विरोधी खेमों पर अब कोई असर नहीं होता। कई वर्षों तक इस नई स्थिति का लाभ भाजपा ने उठाया। भाजपा नेताओं को लेकर कुछ हलकों से तब भी ऐसे शब्द बोले जाते थे, लेकिन तब कथानक पर भाजपा इकॉ–सिस्टम का इतना दबदबा था, वे शब्द बोलने वाले को ही भारी पड़ जाते थे। लेकिन यह बदले माहौल का ही संकेत है कि ऐसे लफ्ज अब जनमत के एक बड़े हिस्से में नया राजनीतिक कथानक गढ़ने का काम करने लगे हैं। भाजपा काफी समय तक विपक्षी नेताओं को प्रहसन–पात्र के रूप में पेश सियासी फायदे उठाती रही, मगर अब सोशल मीडिया–खासकर रील्स के इस्तेमाल से वैसी ही छवि उनके शीर्ष नेताओं को पेश की जा रही है, जिसे एक बड़ा श्रोता वर्ग मिल रहा है। बेशक, यह स्थिति लाने में जेन–जी के आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा के सामने सवाल खड़ा है कि कहानी ऐसे क्यों पलटने लगी है? वे आत्म–मंथन करें, तो शायद उन्हें आभास होगा कि यथार्थ से कटे कथानकों का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। जेन–जी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है। हिंदुत्व की पहचान के साथ श्विश्व गुरुत्व की हैसियत दिलाने के वादों से वह छली गई महसूस कर रही है, तो उसकी वजहें हैं। ये पीढ़ी श्मेक इन इंडियात्य, श्नया भारतत्य, श्देश बदल रहा हैत्य, श्अमृत कालत्य, श्विकसित भारतत्य जैसे नारों को सुनते हुए जब बड़ी हुई, तो उसने पाया कि असल में उसके पास आगे बढ़ने के पहले जितने अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं। तो वह हिसाब मांग रही है। इसका जवाब श्सप्तधारात्य जैसे नए नैटेरिव गढ़ कर नहीं दिया जा सकता। ना ही श्दिमागी नक्सलियोंत्य को अलग–थलग करने जैसे एलान नई परिस्थितियों में अपेक्षित भय पैदा कर सकेंगे।

न्याय का उद्देश्य ही विफल

अजीत द्विवेदी

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव न तो रद्द होगा और न इसे दोबारा कराने के बारे में कोई सोचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो पूछा वह अपने आप में बड़ी बात है। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि श्क्या वह बंगाल में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दे सकता हैत्य? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान लाखों लोगों के नाम काटे जाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह सवाल पूछा और उसके बाद अदालत ने विधानसभा सीटों की हार जीत के अंतर सहित दूसरी कई चीजों का ब्योरा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील ने 31 सीटों का ब्योरा दिया और कहा कि उन सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोट से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर विधानसभा क्षेत्र संख्या 145 यानी दक्षिण 24 परगना की सतगछिया सीट पर भाजपा सिर्फ 401 वोट से जीती, जबकि वहां 8,785 वोट कटे थे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का अंत नतीजा क्या निकलेगा यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। चुनाव तो दोबारा नहीं होंगे। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के दौरान मनमाने तरीके से नाम काटने का चुनाव नतीजों पर असर हुआ है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि भाजपा की जीती 31 सीटें ऐसी हैं, जहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोट से कम है। ऐसी बहुत सी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने भी जीती हैं। इसलिए एसआईआर के असर का आकलन करने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इसके दूसरे कई आधार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आ रहे आंकड़ों में दिख रहे हैं।

असल में सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई के दौरान कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आए। इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा तार्किक विसंगति के आधार पर नाम काटने का है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान एक तार्किक विसंगति की श्रेणी बनाई थी, जिसके तहत 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन सब लोगों की सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण बनाने का आदेश दिया था और उस आदेश पर 19 न्यायाधिकरण बनाए गए थे। तार्किक विसंगति वाले 27 लाख लोगों के अलावा 11 लाख अन्य लोगों ने भी बाद में इन न्यायाधिकरणों के सामने अपील दायर की और नाम काटे जाने के फैसले का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 25 अगस्त को हुई सुनवाई में पता चला कि अभी तक सिर्फ 83 हजार नामों की सुनवाई न्यायाधिकरणों में हुई है। इसकी रफ्तार तो निराश करने वाली है लेकिन नतीजे हैरान करने वाले हैं। जिन 83 हजार लोगों के दस्तावेज जांचे गए और आपत्ति सुनी गई उनमें से 75,443 लोगों की आपत्ति सही पाई गई और न्यायाधिकरणों ने उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया। सोचें, यह कितनी बड़ी बात है! अपील करने वाले लगभग 90 फीसदी लोगों की आपत्ति जायज है। इसका हिसाब लगाएं तो लगभग 34 लाख लोगों के नाम बिना किसी आधार के काट कर उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह ध्यान रखने की बात है कि चुनाव जीतने वाली भाजपा और हारने वाली तृणमूल कांग्रेस के बीच 31 लाख वोट का अंतर है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई बात नहीं है और न कोई गैरजरूरी एक्सरसाइज है। ऐसा होना चाहिए और निश्चित रूप से श्एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट्य इन चार श्रेणियों के लोगों के नाम कटने चाहिए। सभी राज्यों में इन चार आधारों पर नाम कट रहे हैं और उसमें जिसको आपत्ति होती है वह अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, दस्तावेज पेश करता है और सुधार कराता है। लेकिन चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तार्किक विसंगति की एक अलग श्रेणी बना दी और उसमें 27 लाख से ज्यादा नाम काट दिए। हकीकत यह है कि नाम काटने के लिए जो तार्किक विसंगतियां बताई गई हैं वो बेहद अतार्किक हैं तभी जिनके नाम कटे हैं वे दस्तावेज लेकर न्यायाधिकरण के सामने पेश हो रहे हैं और अपना नाम मतदाता सूची में वापस दर्ज करा रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस बात को जानता था कि तार्किक विसंगति के कारण जिनका नाम काट रहे हैं वे जेनुइन मतदाता हैं और दस्तावेज दिखा कर वापस नाम शामिल करा सकते हैं? अगर यह बात साबित होती है तो इसका अर्थ होगा कि चुनाव आयोग ने नतीजों को प्रभावित करने के लिए जान बूझकर इस तरह का काम किया और इससे चुनाव आयोग की साख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि तार्किक विसंगति के कारण नाम काटने से पहले चुनाव आयोग को यह बात समझ में नहीं आई हो कि इनके दस्तावेज सही हैं। आखिर ऐसे 90 फीसदी लोगों के नाम सही पाए जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को यह बात समझ नहीं आई तो यह उसकी अक्षमता का बड़ा सबूत है और अगर समझ में आई फिर भी नाम काटा तो उसकी साख मिट्टी में मिलती है।

एससीओ के मंच से चीन और पाकिस्तान को एक साथ धोकर मोदी ने दुनिया की वाहवाही लूट ली

नीरज

एससीओ शिखर सम्मेलन में वैसे तो सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने संबोधन में तमाम तरह के मुद्दे उठाये लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल

मुद्दों की विविधता और सबको साथ लेकर चलने के जज्बे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही तमाम अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी यह देखकर हैरान हैं कि कैसे मोदी ने मंच पर साथ मौजूद चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया तो वहीं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर चीन को भी आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद पर मोदी ने दो टूक कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं और आतंकवाद को अपनी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंक कभी किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता। वहीं कनेक्टिविटी के नाम पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने चीन को भी साफ संदेश दिया। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी को महज औपचारिक भागीदारी तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के 25 वर्षों की यात्रा को अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने के अवसर में बदलते हुए भारत का स्पष्ट एजेंडा सामने रखा। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्च्युनिटी के जरिये मोदी का संदेश था कि अब केवल घोषणाओं और संवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना होगा। प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे धारदार हिस्सा आतंकवाद पर था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ कार्रवाई केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ, सुरक्षित ठिकानों और पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार करने से साफ इंकार किया। यह संदेश ऐसे मंच से आया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वयं मौजूद थे। भारत की कूटनीतिक उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं हुई। एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने पर स्वीकार की गई बिश्केक डिक्लेरेशन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती दी। घोषणा और शिखर सम्मेलन के अन्य फैसलों में आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए यूनिवर्सल सेंटर संबंधी नियमों को मंजूरी देना सदस्य देशों के बीच समन्वय और सूचना आदान–प्रदान को मजबूत करने वाला कदम है। भारत के लिए विशेष महत्व की बात यह भी रही कि अंग्रेजी को एससीओ के संस्थागत ढांचे में शामिल करने की दिशा में प्रगति हुई। साथ ही भारत द्वारा आगे बढ़ाई गई कई पहलों जैसे– एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव को भी बिश्केक डिक्लेरेशन में स्थान मिला। यह संकेत है कि भारत अब एससीओ में केवल सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाने वाला देश नहीं, बल्कि संगठन के बौद्धिक, सांस्कृतिक और संस्थागत भविष्य को आकार देने वाला सक्रिय साझेदार बन रहा है। मोदी ने अपनी विदेश नीति की व्यापक सोच को भी भाषण में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यूरेशिया की सुरक्षा और शांति का संबंध अफगानिस्तान की स्थिरता से जुड़ा है और भारत वहां विकास तथा मानवीय सहायता जारी रखेगा। पश्चिम एशिया के संघर्षों का उदाहरण देते हुए उन्होंने आगाह किया कि आज की दुनिया में किसी एक क्षेत्र का युद्ध उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उसका असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है, जिसका सबसे अधिक बोझ ग्लोबल साउथ को उठाना पड़ता है। इसलिए भारत का स्पष्ट मत है कि युद्धों और तनावों का समाधान रणभूमि पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नशे के कारोबार को भी क्षेत्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय स्थिरता पर हमला है। इस संदर्भ में एससीओ के तहत सुरक्षा, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नारकोटिक्स से निपटने के लिए बनाए जा रहे केंद्रों को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह आतंकवाद और नार्को–टेररिज्म के खिलाफ भारत की चिंता को व्यापक एससीओ एजेंडे से जोड़ने में सफलता मिली। कनेक्टिविटी पर भी मोदी का संदेश उतना ही स्पष्ट और कूटनीतिक रूप से अहम था। भारत बाजारों को जोड़ने, व्यापार बढ़ाने और विकास के नए रास्ते खोलने वाली सभी पहल का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी किसी भी परियोजना के लिए सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। प्रधानमंत्री का यह संदेश चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल और विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है। भारत लंबे समय से इस परियोजना का विरोध करता रहा है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ऐसे में मोदी ने बिना किसी देश या परियोजना का नाम लिए एससीओ मंच से साफ कर दिया कि कनेक्टिविटी और विकास के नाम पर किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सड़क, रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तीसरे स्तंभ यानि अपॉर्च्युनिटी के जरिए मोदी ने एससीओ सहयोग को आम लोगों से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि युवाओं के लिए कितने अवसर बने, उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले, किसानों को तकनीक से कितना लाभ मिला और नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ। मोदी ने जोर दिया कि एससीओ सहयोग केवल सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि पीपुल–ड्रिवन पार्टनरशिप बनना चाहिए।

पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठनों ने कहा एफसीआरए में प्रस्तावित बदलाव दमनकारी

रवीन्द्र नाथ

इवेंट्स खोजना मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्र और उसके गृह मंत्री से एफसीआरए संशोधन बिल को वापस लेने और इसे और गहन विचार–विमर्श के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 6 अगस्त को नई दिल्ली में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शाह से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठन– जहां मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे तीन राज्यों में ईसाई आबादी बहुत ज्यादा है– फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट (एफसीआरए) बिल, 2026 के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालात के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा है। जेपीसी के लिए यह आम बात है कि वह अपनी राय तय करने से पहले सभी संबंधित पक्षों, जिनमें प्रभावित पक्ष भी शामिल हैं, की बातें सुने। सत्ता पक्ष ने जेपीसी से संसद के मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया था, परन्तु काम की गंभीरता और विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए, जेपीसी को अपनी रपट तैयार करने में देर हो रही है।इस बातचीत की प्रक्रिया में पूर्वोत्तर के कई चर्च काउंसिल और उनके मुख्य संगठन शामिल हैं। इनमें श्असम क्रिश्चियन फोरमश, श्यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ नॉर्थ–ईस्ट इंडियाश और श्नॉर्थ–ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिलश जैसे संगठन शामिल हैं। हालांकि, हमेशा की तरह, जेपीसी में सत्तापक्ष का प्रतिनिधित्व दो–तिहाई और विपक्ष का एक–तिहाई है, फिर भी उम्मीद है कि जेपीसी ईसाई संगठनों के रुख पर उचित ध्यान देगी, जिन्हें एफसीआरए (संशोधन) बिल 2026 के प्रावधान श्दमनकारीश लगते हैं। ईसाई संगठनों को इस बात से राहत मिल रही है कि भले ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधिकारी विदेशी चंदा पाने वाले और उसका इस्तेमाल घरेलू संसाधनों के साथ मिलकर शिक्षा, चिकित्सा और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसे कल्याणकारी कामों में करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने पर तुले हों, फिर भी लोगों के बीच सीएसओ के महत्व को लेकर आम सहमति है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के समय, अक्सर सीएसओ ही सबसे पहले और दूसरे स्तर पर मदद करने वालों के तौर पर काम करते हैं और पीड़ितों के लिए भोजन और आश्रय का इंतजाम करते हैं।2026 के एफसीआरए (संशोधन) विधेयक से पहले, नई दिल्ली ने 2020 में एफसीआरए में संशोधन पास कराए थे। इन संशोधनों के तहत, किसी रजिस्टर्ड संस्था के लिए किसी दूसरी संस्था (भले ही वह उसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो) को धन हस्तांतरित करना मना कर दिया गया था। इसके अलावा, प्रशासन के काम में इस्तेमाल होने वाले विदेशी धन का हिस्सा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। असम क्रिश्चियन फोरम और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रवक्ता ने संवाद को बताया, श्यह बहुत बड़ी कटौती है, जिससे कामकाज को ठीक से चलाना मुश्किल हो जाता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चर्च के प्रशासनिक शाखा में कोई व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। किसी एक व्यक्ति की गलत हरकत के लिए प्रबंधन की कार्यसमिति की छवि खराब करना सही नहीं है।2026 के एफसीआरए (संशोधन) विधेयक में नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव है– विदेश से मिले धन से बनाई गई संपत्तियों को तब भी जब्त किया जा सकता है जब निबंधन प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई हो। किसी संस्था का निबंधन कई स्थितियों में रद्द हो सकता हैय जैसे जब सरकार इसे रद्द कर देय जब नवीकरण) से इनकार कर दिया जाएय औरध्या, जब पुराने प्रमाण पत्र की समय–सीमा खत्म होने से पहले नवीकरण के लिए आवेदन न किया गया हो या मंजूरी न मिले। ऐसी स्थितियों में, संस्था के विदेशी कोष और उनसे बनाई गई संपत्तियां अपने–आप एक तय अधिकारी के नियंत्रण में चली जाएंगी। संस्था के दोबारा निबंधन के बाद ही ये संपत्तियां उसे वापस मिलेंगी, हालांकि दोबारा निबंधन की समय–सीमा अभी तय नहीं की गई है। अगर दोबारा निबंधन नहीं हो पाता है, तो संपत्ति हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी भवन का निर्माण आंशिक रूप से विदेशी धन से हुआ है, तो पूरे भवन को ही जब्त कर लिया जाएगा। फिर संबंधित संस्था को उस हिस्से को वापस पाने के लिए तय अधिकारी के पास आवेदन करना होगा, जिसका भुगतान विदेशी धन से नहीं किया गया था। अपील का दायरा बहुत सीमित है। सक्षम अधिकारी संपत्ति के साथ जो करती है, सिर्फ उसी के खिलाफ अपील की जा सकती है, तथा प्रमाण पत्र का नवीकरण करने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इनकार का आदेश जारी होने से पहले सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसका

मतलब है कि जब अधिकारी नवीकरण के आवेदन की जांच–पड़ताल कर रहे होंगे, तो वह संबंधित पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। 2026 के संशोधन बिल के हर हिस्से पर भाजपा की, या सही कहें तो शाह की मनमानी की छाप दिखती है। इसके उलट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर कोई रोक–टोक नहीं है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए एक बयान में श्दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओश बताया था। आरएसएस का कोई निबंधन नहीं है। एफसीआरए मुद्दे पर चर्चा के दौरान, संवाद के सूत्रों ने ये सवाल उठाएरू श्क्या यह अपनी बड़ी गतिविधियां सिर्फ स्थानीय स्तर पर जुटाए गए धन से चलाता है? क्या इसे विदेश से धन नहीं मिलता? असल में, सीएसओ और एनजीओ के बीच बहुत कम फर्क है।श एक और परेशानी की बात पिछली तारीख से इसके लागू होने का प्रस्ताव है। शाह ने विपक्ष को जुबानी भरोसा दिलाया है कि इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन जानकार सूत्रों ने संवाद को बताया कि इसका कोई भरोसा नहीं है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्र और उसके गृह मंत्री से एफसीआरए संशोधन बिल को वापस लेने और इसे और गहन विचार–विमर्श के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 6 अगस्त को नई दिल्ली में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शाह से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। इसके अलावा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा ने नई दिल्ली से प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्य की चिंताओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

कौशल मिलेगा, रोजगार कहां मिलेगा

अरुण

भारत में केवल 8.26प्रतिशत स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार में हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के दो करोड़ विद्यार्थी शिक्षा और रोजगार के बीच गहरे बेमेल का सामना कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रायरू सामाजिक

प्रतिष्ठा, स्थिर वेतन, सुरक्षित भविष्य जैसी वजहों से सरकारी नौकरी की पात्रता हेतु डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी को सम्मानजनक और स्थायी माना जाता है।विकसित भारत ञ्च2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीति आयोग ने कौशल विकास को पुर्नव्यवस्थित करने की पहल की है। विगत बारह वर्षों में 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास पर गत वर्ष 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लेकिन राज्यों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के योगदान के बावजूद परिणाम असमान बने हुए हैं। अध्ययन ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक रोजगार, शिक्षा–रोजगार–प्रशिक्षण से बाहर के युवा और महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 60 करोड़ नागरिकों को अपने दायरे में लिया है।भारत में केवल 8.26प्रतिशत स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार में हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के दो करोड़ विद्यार्थी शिक्षा और रोजगार के बीच गहरे बेमेल का सामना कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रायरू सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थिर वेतन, सुरक्षित भविष्य जैसी वजहों से सरकारी नौकरी की पात्रता हेतु डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी को सम्मानजनक और स्थायी माना जाता है, इसलिए व्यावसायिक तथा ऑनलाइन शिक्षा पर उनका भरोसा अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में सवाल हैकृनई कौशल व्यवस्था इस बेमेल को दूर करेगी या डिग्रियों के ऊपर कौशल प्रमाणपत्रों की एक और परत जोड़ देगी?अध्ययन के अनुसार मौजूदा व्यवस्था की प्रमुख कमियों में विश्वसनीय करियर मार्गदर्शन का अभाव, स्कूलों में कौशल शिक्षा का सीमित प्रसार, उच्च शिक्षा का उद्योग और अप्रेंटिसशिप से कमजोर जुड़ाव तथा अनौपचारिक कामगारों के लिए प्रशिक्षण की लागत और समय जैसी बाधाएं शामिल हैं। काफी हद तक सैद्धांतिक शिक्षण– प्रशिक्षण का कार्यस्थल की जरूरतों से पर्याप्त मेल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारपरक कौशल का प्रावधान है, पर क्रियान्वयन सीमित है। इसलिए स्कूल स्तर से कौशल शिक्षा, उद्योग की भागीदारी और अप्रेंटिसशिप को रोजगार व आय से जोड़ना जरूरी है। नीति आयोग का सुझाव है कि कक्षा 6 से रोजगारपरक कौशल और कक्षा 9 से श्कौशल ट्रैक्य शुरू हों, जिन्हें स्कूलों की क्षमता और संसाधनों के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाए। उच्च शिक्षा में सामान्य डिग्रियों के बजाय उद्योग आधारित विशेषज्ञता, अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री और श्सीखते हुए कमानेय जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही उद्योग–शिक्षण संस्थानों की भागीदारी, कम अवधि के मॉड्यूल तथा लचीली प्रवेश–निकास व्यवस्था विकसित की जाये। नीति आयोग ने कौशल प्रशिक्षण को बदलती रोजगार मांग से जोड़ने पर जोर दिया हैकृ हरित उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन और उभरते क्षेत्रों के लिए नए कौशल तथा घटते क्षेत्रों में पुनरू कौशल विकास की आवश्यकता बताई है। शिक्षा और रोजगार के बीच पुल बनाने हेतु अप्रेंटिसशिप, एमएसएमई की भागीदारी और करियर मार्गदर्शन को पूरी शिक्षा रोजगार यात्रा का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई है। डिजिटल श्स्किल पासपोर्ट्स और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य–अनुभव को जोड़ा जाए, जिससे पढ़ाई और रोजगार के बीच लचीला आवागमन संभव होगा और सीखना जीवनभर जारी रहे। साझा कौशल–अवसंरचना नेटवर्क को जिला स्तर पर लागू करने का भी सुझाव है। लेकिन इन प्रस्तावों के सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं। शहरी युवाओं में लगभग 70प्रतिशत पसंदीदा करियर वाली नौकरी चाहते हैं, लेकिन कार्यबल में आधे से भी कम को वेतन वाली नौकरी मिलती है और 24 वर्षीय युवाओं में केवल हर तीसरे को ऐसी नौकरी हासिल होती है। लगभग 40प्रतिशत लोग स्वरोजगारी हैं, जिनमें अधिकांश छोटे जीविका आधारित कारोबार होने के कारण दूसरों को रोजगार नहीं दे पाते। युवाओं की वेतन अपेक्षाएं वास्तविक आय से अधिक हैंय सही जानकारी से अपेक्षाएं कुछ घटीं, पर आकांक्षाएं नहीं बदलीं। समस्या केवल आकांक्षाओं की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की क्षमता की भी है। ऐसे में सवाल हैकृकौशल बढ़ाने से रोजगार मिलेगा या कुशल बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी?ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा जब यह स्थानीय आजीविका आधारित कृषि और ग्रामीण उद्योग से जुड़ा हो। गांवों में परम्परागत रोजगार घट रहे हैं, इसलिए मशीनीकरण के साथ नये अवसरकृजैसे डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण या सौर ऊर्जा संयंत्र संचालनकृपर जोर देना होगा। केवल शहरी नौकरियों पर ध्यान देने से ग्रामीण युवाओं में निराशा बढ़ेगी। घटती कुल प्रजनन दर के साथ बच्चों की देखभाल का बोझ कम होने से महिलायें वैकल्पिक रोजगार तलाश रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या अभी भी घरेलू काम जैसे कम वेतन और सीमित प्रगति वाले रोजगारों तक सीमित है। इसलिए उन्हें केवल कौशल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा और योग्यता के अनुरूप सुरक्षित, सम्मानजनक और आगे बढ़ने के समान अवसर वाले रोजगार चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में नया क्या है? इसमें उठाए गए मुद्दे पहले भी विशेषज्ञों की चिंता का विषय रहे हैं। रोजगार सूचना की पहल भारत सरकार ने 1970 के दशक में श्रोजगार समाचारश से शुरू की थी। इसके एक दशक बाद, 1984 में जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने भी ऐसा ही प्रकाशन आरंभ किया। इसमें नौकरी के विज्ञापन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक आलेख प्रकाशित होते थे। असली सवाल हैकृ क्या समस्या केवल कौशल की कमी है? बड़े कौशल–अवसंरचना ढांचे के लिए निवेश कहां से आएगा? जब उच्च शिक्षा की डिग्री ही रोजगार से नहीं जुड़ पा रही, तो अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण कितना कारगर होगा? कक्षा 6 से कौशल शिक्षा शुरू करने का सुझाव सवाल उठाता है।

कमरे में संदिग्ध हालात में मिले नवदंपती के शव,तीन महीने पहले हुई थी शादी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के तिसौली गांव में गुरुवार सुबह एक नवदंपती के शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की शादी करीब तीन महीने पहले हुई थी। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात पति–पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों कमरे में चले गए

और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुरुवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। आवाज देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। कमरे में पत्नी का शव बिस्तर पर मिला, जबकि पति का शव पंखे से लटका हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी शाहगंज गिरेन्द्र सिंह ने बताया कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

2027 में भाजपा के भ्रष्टाचार का होगा अंत –चंद्रशेखर आजाद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। मछलीशहर में सत्ता परिवर्तन यात्रा और बूथ सम्मेलन में शामिल होने से पहले हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के भ्रष्टाचार का अंत होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मछलीशहर विधानसभा का बूथ सम्मेलन कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारियों का पैमाना है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयारी और चुनाव जीतने की रणनीति बताई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान और आरक्षण की रक्षा की बात करती है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है। जनता सरकार की नाकामी देख रही है और आने वाले चुनाव में बदलाव करेगी। उन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी ने अब तक 45 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। जल्द ही अन्य जिलों में भी प्रभारियों की घोषणा की जाएगी। गठबंधन पर बोले– सम्मान और हिस्सेदारी जरूरी

विपक्षी दलों से गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी के रास्ते खुले हैं, लेकिन गठबंधन समान, विचारधारा और विभिन्न मद्दों पर सहमति के साथ ही होगा। उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने पर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 में बने गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए, इसलिए पुराने फार्मूले पर दोबारा विचार जरूरी है। बसपा और आजाद समाज पार्टी के अंतर पर उन्होंने कहा कि दोनों के बीच वैचारिक अंतर है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पांच साल जनता के बीच रहते हैं और लगातार जनहित के मुद्दे उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता में आने पर कक्षा एक से 12 तक मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की कानून–व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि व्यवस्था बेहतर है तो अवैध हथियार और आपराधिक घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही हैं।

जौनपुर सिटी स्टेशन पर सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव को मिली मंजूरी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को बड़ी सौगात मिली है। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22419/22420 गाजीपुर सिटीदृ आनंद विहार टर्मिनल सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से जौनपुर सहित आसपास के जनपदों के यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव का प्रयास सफल रहा। इस संबंध में दूरभाष पर गुरुवार को जानकारी लेने पर राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जौनपुर सिटी स्टेशन पर सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस ट्रेन के ठहराव से

दिल्ली, पूर्वांचल सहित विभिन्न प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, मरीजों और अन्य यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जौनपुर के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। रेलवे से जुड़ी सुविधाओं में विस्तार होने से न केवल यात्रियों की परेशानी कम होगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव से जौनपुर के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक सुविधाजनक रेल विकल्प उपलब्ध होगा। राज्यमंत्री ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति जौनपुर की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा जौनपुर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव जिले के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सुगम, तेज और सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलेगा। जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से भविष्य में भी प्रयास जारी रहेंगे।

अपहरण कर हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में अपहरण कर हत्या की घटना में शामिल एक वांछित अभियुक्त को पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ओमकार साहू पुत्र माधवराम (उम्र करीब 24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ग्राम खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में रह रहा था। उसका मूल निवास ग्राम सिमरिया, जनपद बेमेतरा, छत्तीसगढ़ बताया गया है।पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के कब्जे से मृतक की फॉर्च्यूनर कार की एक चाबी, 1,466 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।पुलिस घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना गाजीपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे को संबंधित धाराओं में तरमीम करने के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को वादिनी की ओर से दिए गए प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 0282/2026, धारा 74 बीएनएस एवं 7ध्8 पॉक्सो अधिनियम के तहत गुड्डू और अमित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।विवेचना के दौरान पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों में शारीरिक शोषण के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट होने पर अभियोग को धारा 70(2) बीएनएस एवं धारा 5(जी)ध्6 पॉक्सो अधिनियम में तरमीम किया गया।पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों अभियुक्त सेक्टर–25 से मुंशी पुलिया जाने वाली सर्विस रोड के किनारे खड़े हैं। सूचना पर थाना गाजीपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी जुटाई जा रही है।गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गुड्डू केवट पुत्र बराती लाल केवट (19 वर्ष) निवासी ग्राम लोहंगपुर, थाना संदना, जिला सीतापुर, हाल पता ग्राम टीकापुरवा, इंदिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ तथा अमित कश्यप पुत्र राम सहाय कश्यप (20 वर्ष) निवासी ग्राम नेवादा बरुआ, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर, हाल पता ग्राम टीकापुरवा, इंदिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ के रूप में हुई है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक आनन्द कुमार, उपनिरीक्षक धनपाल तथा कांस्टेबल भुवन विक्रम चतुर्वेदी शामिल रहे। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 282/2026 दर्ज है।

पीईटी–2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा–2026 (पीईटी–2026) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। आयोग ने इस संबंध में 1 सितंबर को शुद्धि–पत्र जारी किया है।आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 16–परीक्षाध्2026 के अनुसार पीईटी–2026 के लिए विज्ञापन 1 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके तहत पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 निर्धारित थी।अब आयोग ने पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 तक विस्तारित कर दी है। हालांकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 ही रहेगी।

सचिवालय में पांच अनु सचिवों की उप सचिव पद पर पदोन्नति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत एक संयुक्त सचिव को विशेष सचिव तथा पांच अनु सचिवों को उप सचिव के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है। पदोन्नति आदेश 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे।शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गिरीश चन्द्र मिश्रा, वर्तमान में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में तैनात संयुक्त सचिव को विशेष सचिव के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई है। उन्हें विशेष सचिव पद के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (क) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति के बाद उनकी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

कजगांव के कजरी मेले में बिना दुल्हन लौटे दूल्हे और बाराती

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित जफराबाद थाना क्षेत्र के कजगांव स्थित राजेपुर पोखरे पर लगने वाला प्रसिद्ध कजरी मेला बुधवार को सम्पन्न हुआ। सदियों पुरानी परंपरा के तहत इस बार भी दूल्हे और बाराती बिना दुल्हन के ही घर लौट गए। मेले में राजेपुर गांव की ओर से गाजे–बाजे के साथ दूल्हा रवि सोनकर रथ पर सवार होकर पोखरे के पूर्वी तट पर पहुंचा। उसके साथ आए बाराती नाचते–गाते रहे। कुछ देर बाद कजगांव की ओर से भी बड़ी संख्या में बाराती पहुंचे। घोड़े और रथ पर सवार दूल्हे पिंटू सोनकर, करिया, रहीस, राजेश राजभर और पुचुन राजभर भी मेले में पहुंचे। डीजे, भांगड़ा और बैंड–बाजे की धुन पर बारातियों ने जमकर नृत्य किया। इसके बाद पोखरे के पश्चिमी छोर पर दोनों पक्षों के दूल्हे अपने सहयोगियों और पंडित के साथ खड़े हुए। इसके साथ ही मेले की मुख्य परंपरा शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से एक–दूसरे पर आपत्तिजनक इशारे और अभद्र टिप्पणियां की गईं। यह सिलसिला दो घंटे से अधिक समय तक चला। हजारों महिला–पुरुष इस पारंपरिक आयोजन के साक्षी बने। आयोजन समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के दूल्हे और बाराती बिना दुल्हन के अपने–अपने घर लौट गए। मेले में लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं खरीदीं और झूलों का आनंद लिया। बच्चों ने खिलौने खरीदे, जबकि बुजुर्गों ने गृहस्थी से जुड़ा सामान लिया। मेले की व्यवस्था में नगर पंचायत के छोटेलाल यादव, विपिन पटेल, बृजेन्द्र पटेल, हृदय नारायण और राजेश कुमार आदि ने सहयोग किया। संचालन आनंद कुमार और देवेंद्र सिंह ने किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, एसआई मुख्तार राम और प्रभाकर सिंह समेत पुलिसकर्मी लगातार मेले में भ्रमण करते रहे।

अजय राय हत्याकांड में वादी की अदालत में जिरह, भारी सुरक्षा के बीच पेश हुए संजय राय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वर्ष 2003 के बहुचर्चित अजय राय हत्याकांड में बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी संजय राय भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश हुए। एडीजे–6 सुरेंद्र यादव की अदालत में वादी से मुकदमे से संबंधित बिंदुओं पर जिरह की गई। अदालत में हुई कार्रवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया कि मामला आजमगढ़ के लालगंज के तत्कालीन ब्लॉक ज्येष्ठ प्रमुख अजय राय की हत्या से जुड़ा है। दो नवंबर 2003 को जौनपुर क्षेत्र में अजय राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद यह मामला काफी चर्चित हुआ था। अभियोजन के अनुसार, वारदात में कार्बाइन और पिस्टल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान वादी संजय राय के साथ उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह और संजय सिंह समेत अन्य समर्थक मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर में पुलिस बल की तैनाती रही। मामले में कई चर्चित अपराधियों को अभियुक्त बनाया गया है। मुकदमे की सुनवाई लंबे समय से न्यायालय में चल रही है। ऐसे में वादी संजय राय की जिरह को मामले की सुनवाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत में बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। अब सभी की नजरें इस बहुचर्चित हत्याकांड की आगामी न्यायिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को सरकार प्रतिबद्ध : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में इस क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।उप मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के तहत उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों और प्रोत्साहनों की जानकारी अधिक से

अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे किसानों की उपज को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी. एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के अंतर्गत गठित एप्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नवीन निवेश प्रस्तावों का परीक्षण किया गया और प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।समिति ने कुल 12 नवीन आवेदनों पर विचार किया। परीक्षण के बाद 10 प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन स्वीकृति के लिए संस्तुति प्रदान की गई। संस्तुत परियोजनाओं में कैटल फीड, अनाज एवं रिफाइंड मसाले, मूंगफली प्रसंस्करण, फ्रोजन एवं अन्य खाद्य उत्पाद, रेडी–टू–कुक उत्पाद, तेल–आटा–दाल–बेसन निर्माण, दाल मिल तथा फ्रोजन फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। कुछ परियोजनाओं में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।एप्रेजल समिति ने परियोजनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राम मंदिर ट्रस्ट में बढ़ सकती है शरद शर्मा की भूमिका, मीडिया प्रभारी बनाए जाने की अटकलें तेज

लखनऊ, (संवाददाता)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अब मीडिया और प्रचार की जिम्मेदारी को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा को ट्रस्ट में मीडिया प्रभारी की अहम जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। शरद शर्मा लंबे समय से अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मीडिया और प्रचार तंत्र को संभालते रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक वह मीडिया के साथ समन्वय, बयानों और मंदिर से जुड़ी सूचनाओं को मीडिया तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नब्बे के दशक के राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी उनकी सक्रियता रही है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों और बाद में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान शरद शर्मा की मीडिया में लगातार मौजूदगी रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, कार्यक्रमों और बयानों को मीडिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम रही है। यही लंबा अनुभव अब उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीडिया व्यवस्था में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं के केंद्र में ला रहा है ।

निजी केंद्रों में तीन हजार रुपये में होगी स्वाइन फ्लू की जांच, ज्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों में स्वाइन फ्लू की आरटीपीसीआर जांच तीन हजार रुपये में होगी। सीएमओ की अध्यक्षता में मंगलवार को निजी अस्पताल और पैथोलॉजी केंद्र संचालकों की बैठक में यह अधिकतम दर तय की गई। इससे अधिक शुल्क वसूलने वाले केंद्रों पर कार्रवाई होगी। शहर के निजी केंद्र अभी तक स्वाइन फ्लू की जांच के बदले छह हजार रुपये तक शुल्क वसूल रहे थे। इस कारण सभी संदिग्ध मरीज जांच नहीं करवा रहे थे। मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल मेदांता, अपोलो मेडिक्स, आरएमएल पैथोलॉजी, मैक्स, खन्ना डायग्नोस्टिक, चंदन हॉस्पिटल, चरक डायग्नोस्टिक,

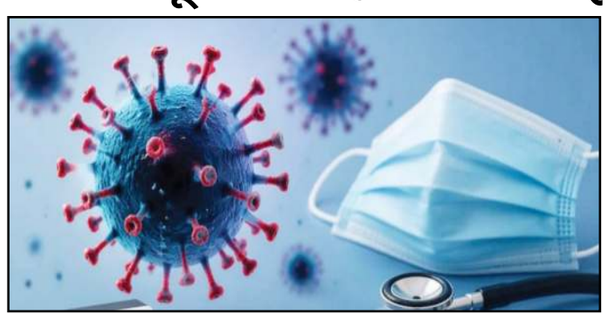

लाल पैथ लैब और नारायण डायग्नोस्टिक के प्रतिनिधियों ने जांच की दर तय करने पर चर्चा की। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि एसजीपीजीआई में इसी जांच के लिए 2400 रुपये शुल्क है। इस आधार पर निजी क्षेत्र में जांच की अधिकतम दर 3000 रुपये तय करने पर सहमति बनी। शहर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को चार नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से दो मरीजों की जांच एसपीजीआई, एक की लोहिया संस्थान और एक की निजी लैब में हुई है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। नए मरीजों को सर्दी–जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी। डॉक्टरों की सलाह पर एच1एन1 की जांच कराई गई। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई।

बीबीएयू में एक माह तक मनाया जाएगा 'राजभाषा हिंदी उत्सव-2026'

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में 1 से 30 सितम्बर 2026 तक 'राजभाषा हिंदी उत्सव–2026' मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस एक माह लंबे उत्सव के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी सहभागिता करेंगे।उत्सव के अंतर्गत हिंदी माह का उद्घाटन, विभिन्न विभागों में हिंदी प्रतियोगिताएं, श्रुतिलेख एवं सुलेख, टिप्पणी एवं प्रारूपण, हिंदी टंकण, राजभाषा सामान्य ज्ञान तथा स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके अलावा सप्त दिवसीय हिंदी कार्यशाला, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं 'आनंद मठ' पर एक दिवसीय कार्यक्रम, दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने उत्सव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी उत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, ज्ञान–परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः अभिव्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की विराट सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है और विविधताओं के बीच संवाद, समन्वय तथा सह–अस्तित्व की भावना को मजबूत करती रही है।कुलपति ने कहा कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन केवल हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दैनिक व्यवहार, कार्यालयीन कार्यप्रणाली, अकादमिक चिंतन, शोध–अनुसंधान और ज्ञान–सृजन में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ना चाहिए। भाषा तभी जीवंत और प्रभावशाली बनती है, जब उसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहज एवं स्वाभाविक रूप से किया जाए।उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज्ञान–परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और भाषायी विविधता के साथ वैश्विक पटल पर नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में भारतीय भाषाओं में ज्ञान का सृजन और प्रसार विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भी भारतीय भाषाओं में शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है। विश्वविद्यालय भाषा और ज्ञान के बीच सशक्त सेतु की भूमिका निभा सकते हैं।प्रो. मित्तल ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सामाजिक न्याय, समानता, ज्ञान और मानवीय गरिमा के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय का प्रयास होना चाहिए।

मिठाई दुकानदार की संदिग्ध मौत, शव छड़ से लटका मिला,पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज

गोरखपुर, (संवाददाता)। देवरिया के भलुअनी थाना क्षेत्र के बारीपुर चौराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार रात एक अधेड़ की मौत हो गई। शव बुधवार सुबह घर के पीछे छड़ से लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खुखुन्दू थाना क्षेत्र निवासी मृतक रामध्यान कुशवाहा पिछले 4–5 वर्ष से बारीपुर चौराहे पर मकान बनवाकर मिठाई की दुकान चलाते थे। चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे। पत्नी सरस्वती देवी का निधन 20 साल पहले हो चुका है। इकलौता बेटा जितेंद्र सूरत में पेंटिंग का काम करता है। घर पर बहू गुड़िया देवी तीन बच्चों के साथ रहती हैं। बहू गुड़िया ने बताया कि मंगलवार रात खाने को कहा तो तबीयत ठीक न होने की बात कहकर मना कर दिया। बुधवार सुबह पड़ोसियों के शोर पर घर के पीछे गई तो शव छड़ से लटका मिला। सूचना पर भलुअनी पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों में मारकर टांगने की चर्चा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

मेंहदावल बाईपास में खड़े ट्रक में भिड़ी लग्जरी गाड़ी, आठ घायल

गोरखपुर, (संवाददाता)। खलीलाबाद शहर के मेंहदावल बाईपास के पास शनिवार को सुबह खड़े ट्रक में लग्जरी गाड़ी भिड़ गई। हादसे में आठ लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। दो की हालत गंभीर देखकर चिकित्सक की टीम ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सभी घायल शादी समारोह से लौट रहे थे। वे गोरखपुर और कुशीनगर के रहने वाले हैं। सहजनवां थाना क्षेत्र के भीटी रावत गांव निवासी सत्यम कुमार (19) ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली में उसके एक दोस्त के यहां शादी थी। इसके चलते बृहस्पतिवार को शाम स्कार्पियो से हरपुर बुदहट निवासी मित्र निक्कू रावत (20), झंगहा थाना के कड़जहां गांव निवासी अभी (20), कुशीनगर के आयुष (19), हर्षित (19), शिवम सिंह (21), टिक्कू वर्मा तथा एक अन्य युवक के साथ गए थे। शुक्रवार को शादी में खाना खाकर रात आठ बजे के करीब वे लोग वापस गोरखपुर के लिए निकले थे। शनिवार को सुबह सात बजे के आसपास खलीलाबाद बाईपास के नीचे वे लोग चाय पीने जा रहे थे। जैसे ही वह सर्विस लेन पर पहुंचे अज्ञात कारणों से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गई।

छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या की कोशिश, प्राथमिकी दर्ज

गोरखपुर, (संवाददाता)। थाना क्षेत्र की दो महिलाओं ने ससुराल पक्ष पर छेड़खानी सहित हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। दोनों मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गुलरिहा पुलिस छेड़खानी, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी सहित एक मामले में हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के एक गांव की महिला का आरोप है कि उसके देवर, ससुर व एक अन्य बृहस्पतिवार की सुबह 10:30 बजे घर में छेड़खानी करने लगे। विरोध पर मारपीट कर गालियां देते हुए गला दबाकर फंदा लगाने की कोशिश करने लगे। पीड़िता ने किसी तरह जान बचाकर पति को सूचना दी। वहीं, एक अन्य मामले में पीड़िता के पिता ने तहरीर में लिखा है कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2016 में सेमरा नंबर एक निवासी युवक से हुई थी। आरोप है कि बेटी के पति, देवर, ससुर, सास पीटते हैं। एक फरवरी 2026 को बेटी के देवर ने पीटा और गला दबाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता अपने मायके चली आई। थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

भाजपा महानगर की बैठक में 2027 की रणनीति पर मंथन, बूथ से मंडल तक सत्यापन पर जोर

वाराणसी, (संवाददाता)। गुलाबबाग स्थित महानगर कार्यालय में मंगलवार को हुई संगठनात्मक बैठक में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के सत्यापन और उसकी सक्रियता पर जोर दिया गया। आगामी राष्ट्रीय प्रवास अभियान के तहत मंडल प्रवासियों को दो दिन में तीन चरणों में संगठन का भौतिक सत्यापन पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में कार्यकर्ताओं से सरकार के विकास कार्यों और वर्ष 2017 से पहले तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक तस्वीर जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया गया। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि जन्माष्टमी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रवास अभियान शुरू होगा। संगठन को धरातल पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए मंडल प्रवासियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान के दौरान दो दिन में संगठन का तीन चरणों में गहन सत्यापन किया जाएगा। पहले चरण में मंडल कार्य समिति का सत्यापन होगा। दूसरे चरण में शक्ति केंद्र संयोजकों का सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में बूथ समितियों का भौतिक सत्यापन होगा। इसका उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उसे और मजबूत करना है। बैठक में कार्यकर्ताओं से सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। स्मार्ट विद्यालयों के निर्माण, नए मेडिकल कॉलेजों, हवाई अड्डों के विस्तार और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत विकास कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया के साथ ही घर–घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं से वर्ष 2017 से पहले और वर्तमान उत्तर प्रदेश की विकास की स्थिति की तुलनात्मक तस्वीर भी जनता के सामने रखने को कहा गया। इस दौरान प्रमील पांडेय, साधना वेदांती, कुसुम सिंह पटेल, अनुराग शर्मा, मनोज सोनकर, विवेक पांडेय और ऋतिक मिश्रा समेत अन्य मौजूद रहे।

तिरुपति की तर्ज पर काशी में बनेगा भव्य श्रीवेंकटेश्वर मंदिर, 15 एकड़ में होगा निर्माण

वाराणसी, (संवाददाता)। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अब काशीवासियों को 1800 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। काशी में ही तिरुपति की तर्ज पर श्रीवेंकटेश्वर मंदिर बनाने की तैयारी है। मंदिर के लिए गंगा किनारे करीब 15 एकड़ जमीन प्रस्तावित की जा रही है। डोमरी और रामनगर क्षेत्र में भी जमीन तलाशी जा रही है। अगले सप्ताह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की टीम वाराणसी पहुंचकर संभावित स्थलों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद जमीन का चयन किया जाएगा। मंदिर परिसर में अस्पताल समेत श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं विकसित करने की योजना है।प्रोजेक्ट से जुड़े एक अफसर के मुताबिक प्रस्तावित परियोजना केवल मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं होगी। मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं के लिए एक बड़े धार्मिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें अस्पताल भी प्रस्तावित है।

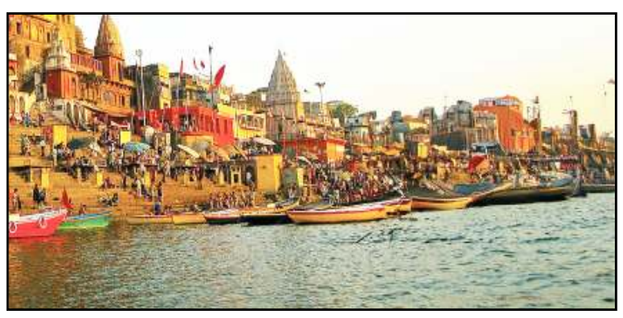

इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन, प्रसाद, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित किए जाने की संभावना है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मंदिर परिसरों में केवल मुख्य मंदिर ही नहीं होता, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं विकसित की जाती हैं। तिरुपति बालाजी में आवास, परिवहन, अन्न प्रसाद, कल्याण मंडप, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवाएं संचालित हैं। जम्मू में स्थापित तिरुपति मंदिर परिसर में भी मंदिर के साथ सुविधाओं के परिसर, कल्याण मंडप, वेद पाठशाला, छात्रावास और कर्मचारियों के आवास जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।

प्रदेश स्तरीय आपदा प्रबंधन बैठक में रेडक्रॉस ने जताई सक्रिय सहयोग की प्रतिबद्धता

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी लेफ्टिनेंट योगेंद्र डिमरी, वी सी के दिशा–निर्देश में प्रदेश के 34 जनपदों के 154 विकासखंडों में आपदा प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ आपदा प्रबंधन, पूर्व तैयारियों तथा विभिन्न विभागों के समन्वय पर चर्चा हुई। आगामी मॉक एक्सरसाइज 10–11 तथा 18 सितंबर को प्रस्तावित है। जिसमें आपदा राहत के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जायेगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने बैठक में प्रतिभाग किया। ये बैठक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन अरविंद कुमार के कार्यालय में आयोजित हुई

डॉ विजय जौहरी ने उपस्थित प्रतिभागियों को मास्क वितरित किए तथा आपदा की स्थिति में आवश्यक सामग्री एवं मानवीय सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने

बताया कि 31 अगस्त को राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा की बैठक हुई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सभापति इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ब्रजेश पाठक के दिशा–निर्देशन में आपदा प्रबंधन में रेडक्रॉस की सहयोगी भूमिका को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया था। जनपद शाहजहांपुर से डॉ विजय जौहरी, डॉ रवि मोहन एवं जिला प्रबंधन समिति के सदस्य अनुज जौहरी ने बैठक में प्रतिभाग कर आपदा प्रबंधन में रेडक्रॉस की सक्रिय भूमिका का प्रस्ताव रखा था।

इसी के अनुपालन में डॉ विजय जौहरी ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत, बचाव, प्राथमिक उपचार एवं मानवीय सेवा में हरसंभव सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगी।

इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा, पशुपालन, अग्निशमन, पीडब्ल्यूडी, होमगार्ड, एनडीआरएफ, पीएसी, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट एंड गाइड, आपदा मित्र लीडर एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि प्रतिभाग हेतु अपेक्षित थे।

बाईपास के दोनों छोर पर पुलिस बूथ बनाए जाने का मामला पहुंचा एडीजी लखनऊ जोन के कार्यालय

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अयोध्या धाम–अम्बेडकर नगर संपर्क मार्ग स्थित गोसाईगंज बाजार से सटकर गए बाईपास के दोनों किनारो (राममहर एवं तेजापुर) पर पुलिस बूथ बनाए जाने का मामला जोर पकड़ने लगा है! मामले को लेकर गोसाईगंज नगर पंचायत की सभासद आरती जायसवाल ने बीते सप्ताह पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ को भी पत्र भेजा है।उम्मीद जताई जा रही है कि उच्चाधिकारियों की

स्वीकृत मिलते ही पुलिस बूथ का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा।गौरतलब हो कि अयोध्या धाम से बसखारी बाजार तक बने फोरलेन सडक निर्माण के दौरान गोसाईगंज बाजार को सुरक्षित रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राम महर से तेजापुर तक(लगभग 6 किमी0) बाई पास सड़क का निर्माण कराया गया था!भेजे गए पत्रों में सभासद जायसवाल ने दर्शाया है बाई पास के दोनों किनारो पर पुलिस बूथ बनने से अपराधियों तक पुलिस जहाँ जल्दी पहुंच जाएगी वही आकस्मिक घटित होने वाली छोटी–बड़ी घटनाओं पर जल्द पहुंचकर स्थित भी कंट्रोल कर लेंगी।

मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से चयनित पांच शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व शाल ओढ़ाकर मुख्य अतिथि ने किया सम्मानित

अयोध्या। गुरुवार को समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय गुलाबबाड़ी मे मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान समारोह एवं शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक सभा डा एस पी सिंह पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा डॉ जितेंद्र प्रसाद मिश्रा थे।कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह व संचालन शिक्षक सभा के जिला महासचिव डा घनश्याम यादव ने किया।प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव का पूरे महानगर क्षेत्र में जगह–जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया स्वागत करने वालों ने मसौधा ब्लॉक पर महानगर उपाध्यक्ष राकेश पांडे व अजय यादव के नेतृत्व में हाशापुर लक्ष्मी कोल्ड स्टोर पर पूर्व प्रधान मुकेश यादव, पार्षद प्रतिनिधि अरौनी पासवान, एवं विद्या भूषण पासी,राम जी समोसे की दुकान के पास पूर्व अध्यक्ष लोहिया वाहिनी शैलेंद्र यादव, दिशा कोचिंग पर अध्यक्ष मुलायम यूथ मंजीत यादव पार्षद राशिद सलीम शिव शंकर शिवा, मिर्जा सनी मेहमूद खान, अनुभव रावत होटल पंचवटी पर विधानसभा अध्यक्ष रक्षा राम यादव, शमशेर यादव राष्ट्रीय महासचिव लोहिया वाहिनी मोहम्मद सोहेल, शिवांशु तिवारी,देवाश्रीवास्तव, अजय मिश्रा, मनूचा कोठी पर महिला महानगर अध्यक्ष अपर्णा जायसवाल, मंसूर प्रधान कोहिनूर पैलेस राष्ट्रीय महासचिव अधिक्तासभा शावेज जाफरी , लाल बहादुर शुक्ला, फरीद कुरैशी, गोविंद यादव, एवं महानगर के पार्षद दल के नेता विशाल पाल टिंकू के नेतृत्व में रीडगंज चौराहे पर महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में महासचिव हामिद जाफर मीसम उपाध्याय चौधरी श्रीचंद यादव प्रवक्ता राकेश यादव सोनू यादव सहित पूरी महानगर कमेटी ने जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद मुख्य अतिथि ने पार्टी कार्यालय पहुंचने पर समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा चुने गए पांच शिक्षको को सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र यादव व कार्यक्रम के संस्थापक पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने प्रशस्ति पत्र व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।इस मौके पर मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी जी के नाम से ये कार्यक्रम 2012 से लगातार होता आ रहा है जो सराहनीय है, इस कार्यक्रम को कराने के लिए कार्यक्रम के संस्थापक पूर्व मंत्री श्री तेज नारायण पांडे पवन व आयोजक जिला अध्यक्ष शिक्षक सभा दान बहादुर सिंह को मै बधाई देता हूं।मुख्य अतिथि ने कहा श्रद्धेय नेताजी ने कार्यकाल में शिक्षकों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे उन्होंने यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई के बराबर कॉपियों के मूल्यांकन का पारिश्रमिक दिया था।ऐसे तमाम बातें है जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने की,आज मौजूदा भाजपा सरकार रोजगार छीनना चाहती है बहुत जाति सभी धर्म पंथ के लोग 2027 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का संकल्प ले चुका है।इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व मंत्रीआनंदसेन यादव पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी, हाजी फिरोज खान गब्बर नी0महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव,नी0 जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम, उपाध्यक्ष चौधरी श्रीचंद यादव, प्रवक्ता राकेश यादव ,प्रदेश सचिव राम अचल यादव, हाजी असद अहमद मोहम्मद हलीम पप्पू जब्बारआली, रियाज अहमद ,छोटे लाल यादव , जिला महासचिव बख्तियार खान चौधरी बलराम यादव,

सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दीया है जिससे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं।कार्यक्रम के संस्थापक पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि नेताजी ने शिक्षकों के हित के लिए अनेकों काम किए,शिक्षकों के सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया और मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नौकरी की सौगात दी,शिक्षकों के हित में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सर्वाधिक फैसले लिये, अब शिक्षकों को पेंशन और ट्रेजरी से समय से वेतन मिल रहा है, यह भी श्रद्धेय नेताजी की ही देन है, आज भाजपा सरकार नौकरी खत्म करना चाहती है , आउटसोर्सिंग पर नौकरी करने पर विवश कर रही उन्होंने कहा मौजूदा सरकार अपने हक की आवाज उठाने पर सड़कों पर निकलेने वाले नौजवानों और महिलाओं पर लाठियां बरसा रही है उन्होंने कहा आज शिक्षित समाज जागरूक है एवं सभी नौजवान व्यापारी किसान बेरोजगार युवा सभी मोहम्मद राशिद शिक्षक सभा के तहसीलदार सिंह,विमल सिंह यादव, प्रभाकर सिंह, अमरनाथ सिंह, प्रदीप तिवारी, रणधीर सिंह, युवराज यादव,अवनीश प्रताप सिंह,, मृत्युंजय सिंह दालसिंगार गौड़ जेपी चौरसिया अशोक साहनी आनंद शुक्ला, डॉ श्याम प्रकाश वर्मा, अजहर अली उस्मानी,, राम कैलाश यादव भानु सिंह,जगन्नाथ यादव,शक्ति जायसवाल, जय सिंह यादव, अंसार अहमद,वीरेंद्र गौतम,विजय यादव रामबख्शयादव,पार्षद रामभवन यादव, राम अजोर यादव, कृष्ण गोपाल यादव,लल्लूर यादव पार्षद , युवराज यादव रामचेत यादव, डा हनुमान मिश्रा डॉ रामचंद्र वर्मा हरिनारायण ओझा, कौशलेंद्र सिंह, लड्डू लाल यादव,दिनेश कुमार विश्वकर्मा, डॉ हरिशंकर यादव,, रामकिशोर त्रिपाठी, रोहित यादव नूर बाबू, मिर्जा सादिक,सैफी बाबूराम अखिलेश पांडे, अर्जुन यादव,, जगत नारायण यादव, मुकेश अजय यादव,,अमन सागर, आदि लोग मौजूद थे।।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो व सहायिका को 8 सितंबर को मिल सकता है बड़ा तोहफा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगामी 8 सितंबर को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है।वे इस मौके पर शहर के जीआईसी मैदान में आगनबाड़ी कत्रियों व सहायिका को सम्मानित कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं और जीआईसी मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।गुरुवार को जिला प्रशासन ने हो रहे तैयारी का निरीक्षण भी किया।मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हैं।वहीं मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो और सहायिकाओं की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।माना जा रहा है कि सरकार की ओर से आंगनबाड़ी से जुड़े लोगों के हित में किसी महत्वपूर्ण घोषणा या सौगात का ऐलान किया जा सकता है।हालांकि संबंध में अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है।जीआईसी मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं पर भी प्रशासन की नजर है।

जीडी शुक्ला बने नये बीकापुर बीडीओ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के विकासखंड बीकापुर के खंड विकास अधिकारी के स्थानांतरण पर जीडी शुक्ला नए खंड विकास अधिकारी बताए गए

हैं।उन्होंने बीकापुर ब्लॉक पहुंचकर अपना कार्यभार ले लिया है।उनके स्वागत के अवसर पर बद्रीनाथ पांडेय एडीओ आरडी, राजेश चौधरी सत्येंद्र यादव,धनंजय मौर्य, नरेंद्र वर्मा,अमरेश कुमार लेखाकार संतोष पांडे ऑपरेटर सहित अन्य लोग रहे।

महिला उप निरीक्षक ने सड़क पर मिला पर्स युवक को लौटाकर पेश किया इमानदारी की मिशाल

अयोध्या।बुधवार देर शाम ड्यूटी पर पर निकली महिला उप निरीक्षक सोनी व श्वेता राठौड़ ने सड़क पर गिरे पर्स युवक को लौट कर ईमानदारी की मिसाल पेश की।इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि बुधवार की देर शाम जब महिला उप निरीक्षक सोनी व महिला उप निरीक्षक श्वेता के साथ गस्त पर निकली थी तभी पुलिस लाइन के पास एक पर्स सड़क पर गिरा दिखाई दिया।इन दोनों पुलिस कर्मियों ने सड़क पर मिले पर्स को जब देखा तो उसमें रखे कागजात के आधार पर लिखे गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया।संपर्क होने के बाद कुंवर कुमार पुत्र स्व. मुकेश कुमार निवासी बेगमगंज गढ़ैया,थाना कैंट,अयोध्या के रूप में हुई।सूचना मिलने के बाद कुंवर कुमार जब देर रात महिला थाना पहुंचे तो पर्स और उसमें रखे सभी दस्तावेज सकुशल वापस मिलने पर कुंवर कुमार ने महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला, उप निरीक्षक सोनी और उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ के प्रति आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय सनातन संघ में मौनी बाबा मठ के पीठाधीश्वर बने प्रदेश सलाहकार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

वाराणसी।राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कन्हैया पांडे जी के नेतृत्व में संगठन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अंबेडकर नगर स्थित मौनी बाबा मठ के पीठाधीश्वर आदरणीय श्री सुरेश कुमार मिश्रा जी को प्रदेश सलाहकार मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय सनातन संघ की वाराणसी इकाई की ओर से इस मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय श्री देवेंद्र पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, प्रदेश प्रभारी श्री विजय शंकर चौबे जी, मंडल सचिव श्री आनंद राय जी, जिला प्रभारी श्री शिवपूजन सिंह जी एवं जिला अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी जी ने श्री सुरेश कुमार मिश्रा जी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की है। पदाधिकारियों ने कहा कि श्री मिश्रा जी के अनुभव और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में संगठन को नई दिशा मिलेगी और सनातन विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।